



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली

Project Implementation Unit, Bareilly

282/01, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बिशप कॉनरोड स्कूल के पास, बरेली - 243 006 (उ.प्र.)

282/01, Greater Green Park, Near Bishop Conrad School, Bareilly - 243 006 (U.P.)

फोन/Tel.: +91-581 3501150 • ई-मेल/E-mail : bareilly@nhai.org, piubareilly@gmail.com



18003/3/PKG-2-1/Forest/2023/प.का.इ.-बरेली/19/74

13.10.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पूर्वी वन प्रभाग

हलद्वानी।

विषय: जनपद उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4/पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-74 (नया रा.रा.-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन **(Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)**.

- संदर्भ:** (1) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 8बी/य0सी0पी0/06/14/2023 दिनांक 28.04.2023.
(2) आपका पत्रांक 6941/12-1 हलद्वानी दिनांक 02.05.2023.
(3) इस कार्यालय का पत्रांक 18003/3/PKG-2-1/Forest/2023/प.का.इ.-बरेली/18338 दिनांक 28.06.2023.

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र 8बी/य0सी0पी0/06/14/2023 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गयी थी।

2. उपरोक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के क्रम में आप द्वारा पत्र दिनांक 02.05.2023 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्तों के अनुपालन करने एवं धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि रु. 6,07,660/- एवं वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए वर्तमान मूल्य रु. 7,57,125/- मांग की गयी थी, जिसके अनुपालन इस कार्यालय के पत्र दिनांक 28.06.2023 द्वारा उपरोक्त धनराशि सहित शर्तों के अनुपालन हेतु आख्या प्रेषित की जा चुकी है।

3. अवगत कराना है कि सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 28.04.2023 के शर्त संख्या-9 में वर्णित एफआरए. 2006 का अनुपालन हेतु संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (5 प्रतियां मूल रूप में) इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक वृक्षों के कटान कराने हेतु कार्यानुमति निर्गत करने का कष्ट करें तथा विधिवत् स्वीकृति (स्टेज-2) हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य समयानुसार पूर्ण कराया जा सके।

संलग्नक: FRA Certificate (5 प्रतियां मूल रूप में)।

(बी0पी0 पाठक)

परियोजना निदेशक



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली

Project Implementation Unit, Bareilly

282/01, ग्रेटर ग्रीन पार्क, बिशप कॉनरोड स्कूल के पास, बरेली - 243 006 (उ.प्र.)

282/01, Greater Green Park, Near Bishop Conrad School, Bareilly - 243 006 (U.P.)

फोन/Tel.: +91-5812523752 • ई-मेल/E-mail : bareilly@nhai.org, piubareilly@gmail.com



18003/3/PKG-2-1/Forest/2023/प.का.इ.-बरेली/18338

28.06.2023

श्रीवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

तराई पूर्वी वन प्रभाग

हलद्वानी।

विषय: जनपद उत्तरप्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4/पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-74 (नया रा.रा.-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन।(Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)

संदर्भ: (1) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या 8बी/य0सी0पी0/06/14/2023 दिनांक 28.04.2023.
(2) आपका पत्रांक 6941/12-1 हलद्वानी दिनांक 02.05.2023.

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र 8बी/य0सी0पी0/06/14/2023 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष सैद्धांतिक स्वकृति जारी की गयी है। सैद्धांतिक स्वकृति के शर्तों के सापेक्ष अक्षरशः अनुपालन आख्या निम्नवत् नियत प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :

S. No.	Conditions	Compliance
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1581 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.581 ha. area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि रु. 6,07,660/- जमा कर दी गयी है। ऑनलाइन भुगतान का साक्ष्य की प्रति संलग्न की जा रही है। (Annexure-I) (ख) वन विभाग से संबंधित है।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य : (क) इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003 28.03.2009, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (P. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3 /2007- एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.7905 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए वर्तमान मूल्य रु. 7,57,125/- जमा कर दिया गया है। ऑनलाईन भुगतान का साक्ष्य प्रति संलग्न की जा रही है। (Annexure-I) (ख) शपथपत्र संलग्न किया गया है। (Annexure-II)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 83 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
7	गार्डललाईन्स में दिए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के आलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	वन विभाग से संबंधित है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
9	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से संनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन हेतु जिला कलेक्टर उधमसिंह नगर से निर्धारित प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.06.2023 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति आपको भी प्रेषित की गयी है। कृपया इस

50

2/4

		संबंध में जिलाधिकारी स्तर से प्रमाणपत्र निर्गत कराये जाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
12	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवे वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
13	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेंगे।	वन विभाग से संबंधित है।
14	नोडल अधिकारी, State CAMPA यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मण्डल अधिकारी को उपलब्ध करावायेंगे।	वन विभाग से संबंधित है।
15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
17	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राष्ट्रीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
19	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/ Backward bearings अंकित हो।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाईल संख्या 11-42/2017 PC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।

25	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
26	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।
27	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	इस शर्त का पालन किया जाएगा।

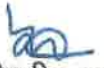
उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नकों की पाँच-पाँच प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक प्रस्ताव की विधिवत् स्वीकृति (स्टेज-2) हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य समयानुसार पूर्ण कराया जा सके।

यह भी अवगत कराना है कि विषयक मार्ग के चौड़ीकरण में बाधक वृक्षों के कटान कराने हेतु कार्यानुमति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(बी०पी० पाठक)
परियोजना निदेशक
२१/१०/२०२२

FORM-I
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate,
District Udham Singh Nagar

No. 885

Dated 06/10/23

TOWHOWSOEVERITMAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.7905** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of National Highways Authority of India, PIU, Bareilly for "**Improvement and up gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 in the State of Uttar Pradesh and Uttarakhand**" in Udham Singh Nagar district of Uttarakhand, falls within the jurisdiction of Udham Singh Nagar district of Uttarakhand villages(s) **Gori Kheda and Chikaghat** in **Sitarganj** Tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.7905** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Uday Raj Singh)

District Magistrate

Udham Singh Nagar

**जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर**

दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :-

1. जिलाधिकारी महोदय उधमसिंह नगर।
2. श्री सन्दीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी।
3. श्री अमन अनिरुद्ध, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंहनगर।

सर्वप्रथम जिला समाज कल्याण अधिकारी उधमसिंहनगर द्वारा अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम समिति की वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा उत्तरा प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4/पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक एन.एच.-24 (नया रा.रा.-30) खण्ड का सुदृढीकरण हेतु 0.7905 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु के विषय में अवगत कराया गया।

ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया की उक्त में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। उक्त के क्रम में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। (संलग्नक-1)

खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी बैठक कार्यवृत्त में परियोजना के निर्माण से किसी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी की भूमि अधिगृहित ना किये जाने तथा वनाधिकारों के प्रभावित ना होने सम्बन्धी उल्लेख किया है। वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। (संलग्नक-2)

उपरोक्त के क्रम में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 0.7905 हे० वन भूमि पर वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत कोई दावे प्राप्त नहीं हुए हैं तथा दावे किसी स्तर पर लम्बित नहीं है। अतः उपरोक्त क्रम में ग्राम सभा एवं उप खण्डस्तरीय समिति के अनापत्ति प्रमाण पत्र के दृष्टिगत जनपद स्तरीय समिति से 0.7905 हे० वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।


(उधम सिंह)
जिलाधिकारी
उधमसिंहनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, उधम सिंह नगर

पत्रांक/ 884 /स.क./जि.स्त.व.अधि./2023-24
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

दिनांक 06 अक्टूबर, 2023

01. उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
02. जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर।
03. श्री अरविन्द कुमार, सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र फुलैया- खटीमा
04. श्रीमती दीपा सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र भीकमपुरी-बाजपुर।
05. श्रीमती नीलम राणा, सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र एंघता-सितारगंज।


जिलाधिकारी
उधमसिंह नगर।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रस्तावित बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड के सुधारीकरण हेतु 0.7905 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बरेली (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, उधमसिंह नगर द्वारा बैठक दिनांक 05/10/2023 को आयोजित की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुए।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री उदय शज सिंह	जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर (अध्यक्ष)	
2.	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी (सदस्य)	
3.	अमन अनिरुद्ध	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर (सदस्य सचिव)	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

कार्यालय उप जिलाधिकारी सितारगंज, जनपद उधमसिंहनगर।

Email address: sdmsitargani@gmail.com

पत्र संख्या 801 / एस0टी0/2023 दिनांक 14.08.2023

सेवा में,

जिलाधिकारी
उधम सिंह नगर।

विषय: उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-74 (नया रा0रा0-30) के किमी 58.400 से किमी 70.800 के चारलेन चौड़ीकरण हेतु 0.7905 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली के कार्यालय पत्र संख्या 18003/3/पी.के.जी.-2-1/फॉरेस्ट/2023/प.का.इ.-बरेली/18539 दिनांक 27.07.2023 के क्रम में आपके कार्यालय के पंजिका संख्या 12/बी0 क्रम संख्या 8397 दिनांक 07.08.2023 के माध्यम से प्राप्त पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली के उक्त पत्र के क्रम में उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-74 (नया रा0रा0-30) के किमी 58.400 से किमी 70.800 के चारलेन चौड़ीकरण हेतु 0.7905 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में समाज कल्याण, वन विभाग, एवं राजस्व विभाग के संयुक्त माध्यम से इस आशय की आख्या कि उक्त परियोजना में प्रभावित ग्रामों गौरीखेड़ा व चीकाघाट में अधिसूचित जनजाति निवास करते हैं अथवा नहीं, के सम्बन्ध में संयुक्त रिपोर्ट/आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 11.08.2023 को समाज कल्याण, वन विभाग, एवं राजस्व विभाग की एक बैठक का आयोजन इस कार्यालय में किया गया, उक्त बैठक का कार्यवृत्त मूल में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर सम्प्रेषित है।
संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(तुषार सैनी)

उप जिलाधिकारी सितारगंज।

बगुल 24/8/23
Received on
24/8/23
Jmca
D5-mu-usa

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सितारगंज

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुल वन भूमि 0.7905 हेक्टेयर का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज की दिनांक 11.08.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सुधा रानी, उप जिलाधिकारी, सितारगंज एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद उधमसिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयरवन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
सिलारगंज (ऊ० सि० न०)

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	हृषीकेश	उपजिलाधिकारी, (अध्यक्ष) / सितारगंज	उपजिलाधिकारी सितारगंज (ऊ० सिंह नगर)
2.	जीवन चंद उप्रेती	उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज (सदस्य) / वन क्षेत्र अधिकारी	उप प्रभागीय वनाधिकारी सितारगंज (ऊ० सिंह नगर)
3.	अमर सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सितारगंज (सदस्य सचिव)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सितारगंज (ऊ० सिंह नगर)
4.	करन सिंह शर्मा	क्षेत्र पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत सदस्य सितारगंज (ऊ० सिंह नगर)
5.	सरतू देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत सदस्य सितारगंज (ऊ० सिंह नगर)
6.	नारज सिंह	क्षेत्र पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत सदस्य सितारगंज (ऊ० सिंह नगर)
7.			क्षेत्र पंचायत सदस्य सितारगंज (ऊ० सिंह नगर)
8.			क्षेत्र पंचायत सदस्य सितारगंज (ऊ० सिंह नगर)
9.			क्षेत्र पंचायत सदस्य सितारगंज (ऊ० सिंह नगर)

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु


 11.8.23
 उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील - सितारगंज, जनपद - ऊधम सिंह नगर
 उपजिलाधिकारी
 सितारगंज (ऊ० सिंह नगर)

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम:- उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सितारगंज

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,.....

उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुल वन भूमि 0.7905 हेक्टेयर का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज की दिनांक11.08.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री तुषार सिंह, उप जिलाधिकारी, सितारगंज एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी
सितारगंज(ऊ0सि0नगर)

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	तुषार सैनी	उपजिलाधिकारी, (अध्यक्ष) सितारगंज	उपजिलाधिकारी सितारगंज (ऊ०सि०नगर)
2.	जीवन चन्द डूंगर	उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज (सदस्य) वन क्षेत्राधिकारी	वन क्षेत्राधिकारी सितारगंज (ऊ०सि०नगर)
3.	गणेश सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सितारगंज (सदस्य सचिव)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सितारगंज (ऊ०सि०नगर)
4.	करन सिंह शर्मा	क्षेत्र पंचायत सदस्य	विखण्ड-सितारगंज (ऊ०सि०नगर) करन सिंह राना सदस्य
5.	सरतू देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत नकुलिया-09 वि०ख०सितारगंज (ऊ०सि०नगर) सरतू देवी सदस्य
6.	गौरज सिंह	क्षेत्र पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत 5 वि०ख०सितारगंज (ऊ०सि०नगर) गौरज सिंह सदस्य
7.			क्षेत्र पंचायत बिडौरा-33 विकास खण्ड-सितारगंज ऊ०सि०नगर (उत्तराखण्ड)
8.			
9.			

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - सितारगंज, जनपद - ऊधम सिंह नगर
उपजिलाधिकारी
सितारगंज (ऊ०सि०नगर)

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सितारगंज

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,.....

उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुल वन भूमि 0.7905 हेक्टेयर का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज की दिनांक 11.08.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री तुषार सेनी, उप जिलाधिकारी, सितारगंज एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी
सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	तुषार सैनी	उपजिलाधिकारी, (अध्यक्ष)	उपजिलाधिकारी सितारगंज (ऊ०सि०नगर)
2.	जालिम चन्द उप्रेती	उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज (सदस्य) वन क्षेत्राधिकारी	वन क्षेत्राधिकारी सितारगंज (ऊ०सि०नगर)
3.	गणेश सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सितारगंज (सदस्य सचिव)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सितारगंज (ऊ०सि०नगर)
4.	करन सिंह राना	क्षेत्र पंचायत सदस्य	Karan करन सिंह राना सदस्य
5.	सबू देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत नकुलिया-09 वि०ख०सितारगंज (ऊ०सि०नगर) सबू देवी सदस्य
6.	निरज सिंह	क्षेत्र पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत बिडौरा-33 वि०ख०सितारगंज (ऊ०सि०नगर) निरज सिंह सदस्य
7.			
8.			
9.			

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु


 उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील - सितारगंज, उपखण्ड - ऊधम सिंह नगर
 सितारगंज (ऊ०सि०नगर)

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सितारगंज

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,.....

उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुल वन भूमि 0.7905 हेक्टेयर का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज की दिनांक11.08.2023.... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री.....तुषार खत्री....., उप जिलाधिकारी, सितारगंज एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी
सितारगंज (ऊधमसिंह नगर)

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	तुषार सैनी	उपजिलाधिकारी, (अध्यक्ष)	उपजिलाधिकारी
2.	जयि चंद उपेनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज (सदस्य)	सितारगंज (ऊ०सि०नगर) वन क्षेत्राधिकारी गडौली वन क्षेत्र, सितारगंज
3.	गणेश सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सितारगंज (सदस्य सचिव)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि०ख०-सितारगंज (ऊ०सि०नगर)
4.	करन सिंह राना	क्षेत्र पंचायत सदस्य	Karan करन सिंह राना सदस्य क्षेत्र पंचायत नकलिया-०२
5.	सरतू देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	सरतू देवी
6.	नारज सिंह	क्षेत्र पंचायत सदस्य	नारज सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत बिडौरा-33 विकास खण्ड-सितारगंज ऊ०सि०नगर (उत्तराखण्ड)
7.			
8.			
9.			

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु


 उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील - सितारगंज, उपखण्ड - ऊधम सिंह नगर
 सितारगंज (ऊ०सि०नगर)

प्रपत्र - 23.2

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सितारगंज

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत कुल वन भूमि 0.7905 हेक्टेयर का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, सितारगंज की दिनांक 11.08.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, सितारगंज एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड सितारगंज परिक्षेत्र के अन्तर्गत भारतमाला परियोजना के अंतर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के अंतर्गत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हेक्टेयर वन भूमि उत्तराखण्ड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली, (प्रयोक्ता अभिकरण) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उपजिलाधिकारी
सितारगंज(ऊधमसिंहनगर)

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	तुषार सैनी	उपजिलाधिकारी, सितारगंज (अध्यक्ष)	उपजिलाधिकारी
2.	जीवा चन्द सैनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी, सितारगंज (सदस्य) / वन क्षेत्राधिकारी	सितारगंज (ऊ०सि०नगर)
3.	गणेश सिंह	सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सितारगंज (सदस्य सचिव)	सहायक समाज कल्याण अधिकारी वि०ख०-सितारगंज (ऊ०सि०नगर)
4.	करन सिंह राणा	क्षेत्र पंचायत सदस्य	Karnan करन सिंह राणा सदस्य
5.	सरदू देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य	क्षेत्र पंचायत नकुलिया-०२ वि०ख०-सितारगंज (ऊ०सि०नगर)
6.	गिरज सिंह	क्षेत्र पंचायत सदस्य	गिरज सिंह सदस्य क्षेत्र पंचायत बिडौरा-33 विकास खण्ड-सितारगंज ऊ०सि०नगर (उत्तराखण्ड)
7.			
8.			
9.			

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - सितारगंज, जिला - ऊधम सिंह नगर
सितारगंज (ऊ०सि०नगर)

परियोजना का नाम:- उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-

तहसील - सितारगंज, जिला - उधमसिंह नगर, उत्तराखंड

उत्तराखंड राज्य के जनपद ऊधम सिंह नगर में भारतमाला परियोजना लॉट-4/पैकेज -2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (New NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 है० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक को संपन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध अनापत्ति प्रणाम पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया की उक्त में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गौरीखेड़ा** एवं **चिकाघाट** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण / संस्था को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य और सही है।


सचिव ग्राम पंचायत
वि.ख. सितारगंज क.सि.नगर
2020-सितारगंज (संवि.नगर)


ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत
वि.ख. सितारगंज क.सि.नगर
ग्राम प्रधान

प्रपत्र - 23.1

दिनांक को ग्राम सभा की संपन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गजराज सिंह	Gajraj Singh
2	Karan Singh Chauhan	Karan Singh
3	कुलवीर सिंह	Kulveer Singh
4	Vishal Chauhan	Vishal Singh
5	Jaspreet Singh	Jaspreet Singh
6	मिहिर कुमार	Mihir Kumar
7	Gaurav Singh	Gaurav Singh
8	Bhavana Pant	Bhavana Pant
9	Savitri	Savitri
10	Viraj Singh	Viraj Singh
11	Rajesh Singh	Rajesh Singh
12	देव सिंह	Dev Singh
13	खंजय सिंह	Khajay Singh
14	रोहन	Rohan
15		
16		
17		
18		

सचिव ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत, जिला, जिला

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत, जिला, जिला
ग्राम प्रधान

Annex - J



PARIVESH
परिवेश

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub "

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

5:34:15 PM

online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of INC principle	Amount to be Paid/ Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
FP/LK/ROAD/146609/2021 Improvement and up-gradation of NH-74 (New NH-30) stretch from Bareilly to Sitarganj under Bharatmala Pariyojana Lot-4/Package-2 In the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand	ROAD1466092021559611	61146609559	28 Apr 2023	CA: 709539/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 757125/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1466664/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 31 May 2023 Nodal Officer On : Union Bank Of India Bank Name : NEFT/RTGS (Challan) Mode of Payment : 31 May 2023 Challan Generated On : 09 Jun 2023 Transaction Date :	Demand Letter Generated Challan

Annexure-II

परियोजना का नाम- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन | (Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)

वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि की शपथपत्र

मैं, बी पी पाठक, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वचन देते हूँ कि प्रगत परियोजना जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे. वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के निर्माण हेतु यदि विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार को प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा मांग के अनुसार किया जायेगा ।



(बी पी पाठक)

परियोजना निदेशक
पी.आई.यू., बरेली

Annexure-II

परियोजना का नाम- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन | (Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)

वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि की शपथपत्र

मैं, बी पी पाठक, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की और से वचन देते हूँ कि प्रगत परियोजना जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे. वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के निर्माण हेतु यदि विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार को प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा मांग के अनुसार किया जायेगा ।



(बी पी पाठक)

परियोजना निदेशक
पी.आई.यू., बरेली

Annexure-II

परियोजना का नाम- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन | (Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)

वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि की शपथपत्र

मैं, बी पी पाठक, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वचन देते हूँ कि प्रगत परियोजना जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे. वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के निर्माण हेतु यदि विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार को प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा मांग के अनुसार किया जायेगा ।


(बी पी पाठक)

परियोजना निदेशक
पी.आई.यू., बरेली

Annexure-II

परियोजना का नाम- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन | (Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)

वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि की शपथपत्र

मैं, **बी पी पाठक**, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वचन देते हूँ कि प्रगत परियोजना जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु **0.7905** हे. वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के निर्माण हेतु यदि विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार को प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा मांग के अनुसार किया जायेगा ।


(बी पी पाठक)

परियोजना निदेशक
पी.आई.यू., बरेली

Annexure-II

परियोजना का नाम- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन | (Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)

वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि की शपथपत्र

मैं, बी पी पाठक, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वचन देते हूँ कि प्रगत परियोजना जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4 / पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे. वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के निर्माण हेतु यदि विशेष समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो राज्य सरकार को प्रयोक्ता अधिकारण द्वारा मांग के अनुसार किया जायेगा ।


(बी पी पाठक)

परियोजना निदेशक
पी.आई.यू., बरेली

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बरेली
Project Implementation Unit, Bareilly

243/008, ग्रीन पार्क, ब्रिगेड कॉन्वेंट स्कूल के पास, बरेली - 243 008 (उ.प्र.)

243/008, Green Park, Near Bishop Convent School, Bareilly - 243 008 (U.P.)

फोन/Tel: +91-5812523752 • ई-मेल/E-mail : bareilly@nhai.org, piubareilly@gmail.com



18003/1/For-Gen-1/2021/प.का.इ.-बरेली/18240

10.06.2023

सेवा में,

जिलाधिकारी

ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)।

विषय: उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4/पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक एन. एच.-24 (नया रा.रा.-30) खण्ड का सुदृढीकरण हेतु 0.7905 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन के संबंध में (Proposal no.- FP/UK/ROAD/146609/2021).

संदर्भ: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बो/यू०सी०पी०/०६/१४/२०२३/एफ.सी./१०७ दिनांक 28.04.2023.

महोदय,

कृपया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का संदर्भित पत्र दिनांक 28.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निम्नलिखित कार्य हेतु उत्तराखण्ड ऊधमसिंह नगर में परियोजना में प्रभावित 0.7905 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-1) प्राप्त हुई है।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा दी गयी सैद्धांतिक स्वीकृति (स्टेज-1) के शर्त सं.-9 में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा जारी FRA Certificate की मांग की गयी है, जो वन प्रस्ताव में पाँच मूल प्रतियों के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

3. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के स्तर से जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र (FRA Certificate) के प्राख्य की पाँच प्रतियां हस्ताक्षर हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक कार्य हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत FRA Certificate पाँच प्रतियों में जारी करने का कष्ट करें, जिससे कि वन प्रस्ताव पर विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक: FRA Certificate के प्राख्य की पाँच प्रतियां।

भवदीय,

(बी.पी. पाठक)

परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, तराई पूर्वी, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE,
DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/१४/२०२३/एफ.सी. 107

दिनांक: 28/04/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4/पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/Road/146609/2021)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 1685/FP/UK/Road/146609/2021 दिनांक 13.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.04.2023 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार- जनपद- उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्य में भारतमाला लॉट-4/पैकेज-2 के तहत बरेली से सितारगंज तक NH-74 (new NH-30) खण्ड का सुधारीकरण हेतु 0.7905 हे० वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1581 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 1.581 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।

ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के०एम०एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस०एम०सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू०एल०एम०पी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राष्ट्रीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
19. संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
20. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
22. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
23. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
24. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
25. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।
26. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
27. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic/in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे) 113
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(गजेन्द्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)